मार्च, 2023 माह के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियों का मासिक सारांश।

I. स्वच्छ भारत मिशन

i. सभी 4,715 शहरों/कस्बों को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) घोषित किया गया है, जिनमें से 4,355 शहरों को तीसरे पक्ष के सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया गया है, 3,547 शहरों को ओडीएफ+ के रूप में प्रमाणित किया गया है, 1191 शहरों को ओडीएफ++ और 14 शहरों (इंदौर, सूरत, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), तिरुपति, चंडीगढ़, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, हैदराबाद, ग्रेटर विशाखापत्तनम, कराड, पंचगनी, भोपाल, बारामती और मैसूर) को जल+ के रूप में प्रमाणित किया गया है।

ii. 3,326 से अधिक शहरों में 67,407 शौचालय "एसबीएम शौचालय" के नाम से गूगल मानचित्र पर लाइव हैं।

iii. स्वच्छता ऐप नागरिकों को संबंधित नगर निगम द्वारा नागरिकों की शिकायतों को दूर करने में सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में उभरा है। स्वच्छता ऐप के कुल 2.08 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, जिन्होंने 2.55 करोड़ शिकायतें दर्ज की हैं, जिनमें से 2.39 करोड़ शिकायतों का समाधान किया जा चुका है ,इस प्रकार 94% से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया है।

iv. स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह 2022 के तहत 01 अक्टूबर 2022 को जीएफसी 2022 का परिणाम घोषित किया गया।कचरा मुक्त शहरों (जीएफसी) के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत 7-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या 1 है, 5-स्टार प्रमाणन वाले 11 शहर है, 3-स्टार प्रमाणन वाले 199 शहर है और 1 स्टार वाले प्रमाणन 234 शहर है।जीएफसी मूल्यांकन अब तिमाही आधार पर आयोजित किया गया है। जीएफसी के तहत यूएलबी से 28 फरवरी, 2023 तक कुल 3,356 आवेदन प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदनों का डेस्कटॉप मूल्यांकन (डीए) प्रक्रियाधीन है। 10 अप्रैल, 2023 तक कुल 1606 शहरों का मूल्यांकन किया गया है, जिनमें से 494 यूएलबी ने डीए में सफल रहें हैं।

v. 8 मार्च को **महिला दिवस** के लिए, माननीय मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने **स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0** के तहत 3-सप्ताह के महिला-नेतृत्व वाले स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया। अभियान का उद्देश्य वूमन इन सेनिटेशन से परिवर्तित करके वूमन लैंड सेनिटोशन संबंधी बदलाव का संज्ञान लेना और इस प्रसन्ता को साझा करना है ।

vi. **विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च 2022 को आयोजित 5वीं स्वच्छ वार्ता** के दौरान आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 'छोटे शहरों में प्रयुक्त जल प्रबंधन' विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया था।

vii. **स्वच्छोत्सव 2023 अभियान** के रूप में, मिशन ने **'स्वच्छ मशाल मार्च'** के रूप में 3,000 से अधिक शहरों के नागरिकों को एकजुट किया । इस मशाल मार्च ने 28 से 31 मार्च तक लगभग 3,000 शहरों के वार्डों को एकजुट किया और इसका नेतृत्व महिला चेंजमेकर्स, एसएचजी सदस्यों, सामाजिक प्रभावकों, तथा राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा किया गया।

II. स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम)

i. 81,045 करोड़ रुपये की 7870 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 1,06,385 करोड़ रुपये की 5,627 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। मार्च 2023 क महीने में, 1,330 करोड़ रुपये की 151 अतिरिक्त परियोजनाएँ पूरी की गई हैं।

ii. **नेशनल यूथ कॉन्क्लेव 2023 (13-14 मार्च 2023)**

भारत का सबसे बड़ा युवा शिखर सम्मेलन- 'नेशनल यूथ कॉन्क्लेव' स्मार्ट सिटीज मिशन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग और राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एनआईयूए) द्वारा आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम 2023 में भारत के G20 प्रेसीडेंसी के तत्वावधान में आयोजित किया गया था और इसे शहरी 20 और यूथ 20 भागीदार समूहों के साथ संरेखित किया गया था। 13-14 मार्च 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित इस दो दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया । यह कॉन्क्लेव यू 20 और वाई 20 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार-विमर्श करने और भविष्य के सशक्त नेताओं को तैयार करने के लिए इन्हें एक साथ लाया।

अर्बन 20 स्थापना बैठक का आयोजन अहमदाबाद, गुजरात में किया गया था, जिसमें आवास और शहरी कार्य और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के माननीय मंत्री ने कहा है कि "अर्बन 20 को ग्लोबल पीयर लर्निंग के लिए एक बडे अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए"।सीखने की इस उत्कृष्ट महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में देश भर के युवा, राष्ट्रीय नेता, विशेषज्ञ, छात्र, शोधकर्ता और नवप्रवर्तक एक साथ आए ताकि कुछ जरूरी विषयों पर चर्चा की जा सकें और शहरों और समुदायों को रहने और फलने-फूलने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के बारे में एक-दूसरे से सीखा जा सकें।

कॉन्क्लेव की कुछ प्रमुख घटनाएं:

- **रिलीज - एसएएआर संग्रह 1.0** देश के 15 प्रमुख कॉलेजों ने एसएएआर कार्यक्रम (स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिक टुवर्ड्स एक्शन रिसर्च) के तहत अभिनव शहरी परियोजनाओं के 75+ केस स्टडीज का दस्तावेजीकरण किया है।
- **अन्य रिलीज** - प्रजातंत्र, इंडियन स्मार्ट सिटीज फेलो प्रोग्राम (आईएससीएफपी), नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन (एनयूडीएम), द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम (टीयूएलआईपी)

और नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म (एनयूएलपी) द्वारा लेखों, केस स्टडीज और सूचनाओं के संग्रह रिलीज किए गए ।

- **लॉन्च - एसएएआर संग्रह** 2.0 प्रत्येक स्मार्ट सिटी को कम से कम एक अकादमिक/अनुसंधान संस्थान के साथ जुडने और कार्यान्वित परियोजनाओं के कम से कम 3 केस स्टडी तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये नवोन्मेषी शहरी पहलों की प्रतिकृति के लिए संदर्भ दस्तावेज बनेंगे।
- **प्रदर्शनी** - आयोजन स्थल पर 2 दिनों के लिए एसएएआर और एनएमसीजी (स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन) के तहत अभिनव शहरी परियोजनाओं पर दो स्मार्ट समाधान प्रदर्शनी लगाई गई थी।
- **पूर्ण सत्र** - बेहतर शहरी भविष्य के लिए कौशल और नवाचार को उत्प्रेरित करने वाले जलवायु परिवर्तन लचीलापन, प्रशासन और योजना अवसंरचना संबंधी के लिए विषयों पर चर्चा की गदई।

III. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

i. सभी राज्यों के लिए 77,640 करोड़ रूपये की राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब तक, 83,096 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी गई है। कुछ राज्यों ने अपने अनुमोदित एसएएपी से अधिक परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसमें अतिरिक्त राशि राज्यों/यूएलबी द्वारा वहन की जाएगी। 36,208 करोड़ रुपये की 4,841 परियोजनाओं के लिए कार्य पूरा हो चुका है और 46,526 करोड़ रुपये की 1,044 परियोजनाओं के लिए कार्य जारी है। कुल मिलाकर, अमृत परियोजनाओं का लगभग 69,901 करोड़ रुपये का वास्तविक कार्य पूर्ण हो चुका है/चल रहा है, जिसका अर्थ है कि लगभग 90% वास्तविक कार्य पूरा हो चुका है।

ii. अभी तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना कार्यान्वयन (पूर्ववर्ती जेएनएनयूआरएम की पात्र परियोजनाओं सहित), प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (एएंडओई), सुधार प्रोत्साहन, और उप-योजनाओं के तहत 25 चयनित शहरों में 'अमृत शहरों में जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करना' और 'लोकल एरिया प्लान (एलएपी) और टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस)' के लिए 38,134 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

IV. दीनदयाल अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई/एनयूएलएम)

i. 7,547 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाए गए हैं; 17,103 एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड दिया गया हैं; 23,953 उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण और प्रमाण-पत्र दिए गए थे थे; 10,346 प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्लेसमेंट दिया गया; 10,931 लाभार्थियों को व्यक्तिगत और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए ऋण की सहायता दी गई और एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत एसएचजी को 23,983 ऋण दिए गए।

V. पीएम पथ-विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएमएसवनिधि)

i. पीएम पथ-विक्रेता आत्म निर्भर निधि (पीएमएसवीनिधि) के तहत, 64,77,777 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 48,58,284 स्वीकृतियां और 43,08,613 ऋण वितरण किए गए हैं।

ii. मार्च, 2023 के दौरान मिशन के तहत कुल 55.827 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं।

VI. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)/सभी के लिए आवास (एचएफए)

i. शुरूआत के बाद से, मिशन ने 1.20 करोड़ आवासों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 110.01 लाख आवास निर्माण हेतु लिए गए है, जिनमें से 73.08 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है/सुपुर्द किए जा चुके है।

ii. मार्च, 2023 के दौरान पीएमएवाई मिशन के तहत कुल 2993.89 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं।

VII. आवास

i. नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों/ ने रेरा के तहत नियमों को अधिसूचित किया है, जो नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है।

ii. **32** राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (नियमित-26, अंतरिम-06) की स्थापना की है। लद्दाख, मेघालय और सिक्किम ने नियमों को अधिसूचित किया है तथापि प्राधिकरण अभी स्थापित किया जाना है ।

iii. **28** राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने रियल एस्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल (नियमित-24, अंतरिम -04) (अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं) की स्थापना की है।

iv. **30** राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के नियामक प्राधिकरणों ने रेरा के प्रावधानों के तहत अपनी वेबसाइटों को चालू कर दिया है। (अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर चालू करने की प्रक्रिया में हैं)।

v. देश भर में **1,01,598** रियल एस्टेट परियोजनाओं और **72,369** रियल एस्टेट एजेंटों ने रेरा के तहत पंजीकरण कराया है।

vi. देश भर में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों द्वारा **1,06,891** शिकायतों का निपटान किया गया है। मार्च, 2023 माह के दौरान 396 परियोजनाओं एवं 481 एजेंटो का पंजीकरण किया गया है।